शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.]

Shri Daji: Is the Government aware that after the summer vacations are over, a new rush begins? Will those who want to seek admission in Delhi be provided with schools near their localities?

Shri M. C. Chagla: I want to assure my hon. friend that every effort will be made to see that every student in Delhi will have the facilities afforded to him which are necessary.

श्री अचल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरी इन्फार्मेशन कब तक सुलभ हो जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : थोड़ी बहुत इन्फार्मेशन मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : पूरी कब हो जायेगी।

श्री मु० क० चागला : जैसा मैंने कहा, जल्दी ही मैं इन्फार्मेशन दूंगा।

Shrimati Akkamma Devi: In view of the fact that there is always a rush for admission right from the primary stage to the higher secondary stage at the beginning of the reopening day, and in view of the fact that private organisations are willing to open some schools to satisfy the needs of the student population, may I know whether Government will not only sanction such schools, but render adequate financial aid to such private organisations?

Shri M. C. Chagla: Yes, Sir. In our country, education is a mixed one, both public and private, and to the extent that proper private schools are going to be opened, every assistance will be given to such organisations.

श्री क० ना० तिवारी : अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि पूरी इन्फार्मेशन नहीं है, कुछ है। वह कौनसी इन्फार्मेशन है जो हाउस को दी जा सकती है?

Shri M. C. Chagla: The available information is this: 11,000 additional students have such admission at middle and higher secondary stages in the secondary schools in Delhi. Over 47,000 children in the age group of six to ten years are expected to seek admission. The Corporation has made provision to admit all the children who seek admission at the primary level. They have also made provision for admitting 9,000 additional children in the middle schools.

With regard to the number of new Higher Secondary Schools, 17 middle schools will be upgraded by Government, and six middle schools will be upgraded by private agencies. With regard to middle schools, the Corporation is upgrading 50 primary schools. With regard to primary schools, the Corporation is opening 50 new schools. This is the information available so far.

दिल्ली का भावी ढांचा

*१२५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के भावी प्रशासनिक ढांचे की कोई रूपरेखा तैयार हो चुकी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक यार हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) . मामला अभी विचाराधीन है।

[(a) and (b). The matter is still under consideration.]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बार बार इस प्रश्न का उत्तर यह दे दिया जाता है कि मामला अभी विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी कठिनाइयां आ रही हैं जिनसे इस विषय पर अब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है।

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): बहुत दफे इस पर विचार हुआ, मशविरा हुआ, लेकिन जब तक सब तरफ से एक राय नहीं होती तब तक कोई फैसला करना मुश्किल था। जो कुछ अब तक सोचा गया था उसके बारे में पूरी रजामन्दी अभी तक हासिल नहीं हो सकी है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी ने जो दिल्ली के भावी ढांचे के सम्बन्ध में कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुला कर बातचीत की थी, क्या उसमें कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों ने इस प्रकार का कुछ सुझाव दिया है कि दिल्ली का सम्भावित ढांचा बनाने के लिये नये सिरे से चुनाव कराये जायें। यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में आप के क्या विचार हैं।

श्री नन्दा : इस पर कोई खास विचार करने की जरूरत नहीं समझी गई।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि सरकार राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बार बार परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार करती है और इस सवाल को उठाया जाता है।

श्री नन्दा : यह सवाल उठा था और इसके लिये यह फैसला हुआ था कि इस पर सोचा जाये और कुछ तबदीली की जाये। किस किस्म की तबदीली हो, किस हद तक इसमें कारपोरेशन को नये अधिकार दिये जायें, इसके बारे में बातचीत हुई। लेकिन ऐसा मालूम होता था कि अभी सब को एक जगह पर लाने के लिये पूरी तैयारी नहीं है।

Shri D. C. Sharma: The public and the citizens of Delhi want an Assembly of the Himachal Pradesh type for Delhi. May I know from the Government what stands in the way of their conceding that legitimate demand of the citizens of Delhi?

Shri Nanda: The hon. Member describes it as a legitimate demand. I do not enter into that question. This matter has been settled, discussed and settled.

Shri S. M. Banerjee: I would like to know whether it is a fact that all the political parties, whether Opposition or the ruling party, are unanimous on this question that Delhi's future should be decided and some autonomy should be given. I want to know which parties or persons are standing in the way, and why it is delayed when a definite assurance was given by the late lamented Pandit Gobind Ballabh Pant.

Shri Nanda: That assurance was in terms of expanding the functions of the Corporation, and investing it with larger powers, so that there may be much greater autonomy in its operations. Now, it is on that basis that the talks and the negotiations proceeded. Somehow, it was not possible to arrive at an agreement.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : दिल्ली के प्रशासनिक क्षेत्र में पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को लेने के विचार की बाधा तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है।

श्री यु० सिं० चौधरी : क्या कारण है जिसकी वजह से सरकार सोच रही है कि दिल्ली के वर्तमान राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन किया जाये।

श्री नन्दा : यह तमाम बातें पहले हो चुकी हैं।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि स्वर्गीय प्राईम मिनिस्टर जी ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली के ढांचे को स्विस कैन्टन्स की प्रकार का रखा जायेगा, और

इस प्रकार के ढांचे के लिये लोगों का इंटरव्यू भी हो चुका था। अखबारों में आया था कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के ढांचे को बदला जायेगा। तो क्या सरकार के पास कोई स्कीम तैयार है।

श्री नन्दा : वह आउट लाइन या स्कीम स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ चर्चा व परामर्श करके तैयार की गई थी; उनसे परामर्श करके ही वह स्कीम बनाई गई थी मगर उससे कुछ भाइयों को सन्तोष नहीं है।

श्री बड़े : मेरा तो प्रश्न है कि सन्तोष क्यों नहीं हुआ। मन्त्री महोदय ने अभी बतलाया कि कुछ भाइयों को उससे सन्तोष नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : यह बतलाना जरूरी नहीं है।

Shri Bade: We want your protection.

Mr. Speaker: Exactly, it is I who want protection at this moment.

Shri Bade: Who are the persons who are coming in the way?

Mr. Speaker: I cannot insist on that. Next question.

Indian Education Service

\+

*126. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Dhaon:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri B. K. Das:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether any progress has been made in bringing an Indian Education Service into existence and if so, the broad outlines thereof;

(b) whether the idea has generally been approved by the State Governments; and

(c) the steps proposed to be taken in this connection?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). All the State Governments except Punjab, Madhya Pradesh and Maharashtra have agreed in principle to the formation of an All India Educational Service. Negotiations with these three States are still in progress. Full details of the Scheme will be worked out after the consent of all the States has been received.

I may amend this answer to the extent that as far as Maharashtra is concerned, I have had talks with the Maharashtra Government and there is every hope that they will accept this in principle. The only question is as to what particular posts from the All India Education Service the Maharashtra Government could be expected to take up and what officers would be posted there. Therefore, actually we are still negotiating with Punjab and Madhya Pradesh.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि जिन जिन राज्यों ने इस इंडियन एजुकेशन सर्विस की स्कीम को मान्यता नहीं दी है उन्होंने क्या कोई कारण भी बतलाये हैं कि किस किस कारण से उन्होंने इसे मान्यता नहीं दी है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे पता है पंजाब को और डिटेल्स की जरूरत है। वह यह कहते हैं कि यह एक सर्विस होगी और वह एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स होंगे या एजुकेशनल आफिसर्स होंगे और इस बारे में पंजाब के साथ डिस्कशन चल रहा है...

श्री हरि विष्णु कामत : मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या कहा है ?

श्री मु० क० चागला : मध्य प्रदेश ने कोई खास प्वाएंट नहीं लिया है लेकिन क्लियर